विवरण

20 सेमी. से अधिक/प्रति वर्ष की दर से जल स्तर में गिरावट को दर्शाने वाले जिलों की सूची (दीर्घावधि विश्लेषणों पर आधारित)

क्र.सं.	जिला	ब्लाक	
1.	आगरा	अचनेरा	0.22
		बरौली अहीर	0.42
		बिचपुरी	0.29
		फतेहाबाद	0.37
		फतेहपुर सिकरी	0.32
		जगनेर	0.24
		जसराना	0.45
		खनौली	0.43
		खेरागढ़	0.24
		पिनाहट	0.66
		मेयान	0.22
2.	अलीगढ़	गेंगरी	0.30
		हसेन	0.25
		हाथरस	0.21
		लौधा	0.28
		तप्पल	0.30
3.	इलाहाबाद	कारा	0.57
		मंझनपुर	0.24
		मउआइमा	0.30
		नेवाड़	0.21
		बरसावन	0.51
		सिराथु	0.26
4.	आजमगढ़	तरवा	0.27
5.	बदायूं	बिनवार	0.37
		इस्लाम नगर	0.29
		उसावन	0.25
6.	बहराइच	जरवाल	0.24
		नवाबगंज	0.24
7.	बलिया	बैरिया	0.23
		गरवार	0.25
		रेवती	0.23
8.	बांदा	बावेरू	0.29
		कामासिन	0.59
		मऊ	0.43
		तिंदवारी	0.60
9.	बरेली	दरियाबाद	0.22
		हरख	0.27
10.	बरेली	दियारा	0.44
		मीरगंज	0.32
		रामनगर	0.30

पारम्परिक सिंचाई प्रणाली

2630. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार गांवों में तालाबों, पोखर आदि का विकास करके देश की पारम्परिक सिंचाई प्रणाली को पुन: प्रारंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में वर्षा के माध्यम से उपलब्ध जल का सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत से भी कम मात्रा में उपयोग होने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में सिंचाई के प्रयोजनार्थ वर्षा के जल की उपलब्धता के संबंध में सरकार का क्या आकलन है और उक्त तालाबों और पोखरों इत्यादि का विकास करके इसकी उपलब्धता को किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें स्थानीय स्थल स्थितियों के आधार पर तालाबों, पोखरों आदि जैसी परम्परागत सिंचाई प्रणालियों के अलावा आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को भी क्रियान्वित कर रही हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध वर्षा जल के 50% से भी कम जल का देश में सिंचाई के लिए प्रयोग किये जाने की संभावना है। तालाबों और पोखरों आदि का विकास करके सिंचाई के लिए वर्षा जल की उपलब्धता को बढ़ाने के बारे में कोई अलग अनुमान नहीं लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त जल भण्डारण परियोजना

2631. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन नदी के जल के बंटवारे के संबंध में सहमति न होने के कारण गंगऊ नामक स्थान पर संयुक्त जल भण्डारण परियोजना पूर्ण नहीं हो पा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के काली मिट्टी वाले जिला बांदा के लिए इस परियोजना का भारी महत्व है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के वरियापुर बियर के बाएं तट से निकलने वाली नहर के लिए जल की आपूर्ति इसी परियोजना से संभव होगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) गंगऊ परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के बाद में इस परियोजना की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

2632. **प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अनेक सिंचाई परियोजनाएं सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर लिया जायेगा;

(घ) इनके लिये कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) विवरण अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 186 अनुपत्र संख्या 47]

(ङ) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को कितनी शीघ्रता से मानती है।

Central Assistance for Madduvalasa Project

2633. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether additional Central assistance has been sought by Andhra Pradesh Government for the Madduvalasa Project;

(b) if so, what is the additional Central assistance sought for this Project;

(c) the quantum of Central assistance released in this regard;

(d) whether the request of Andhra Pradesh Government has been complied with; and

(e) if not, status of the request?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (e) An amount of Rs. 14.34 crores was approved for Maduvalasa Project as requested by Andhra Pradesh in June, 1998 as Central Loan Assistance under Accelerated Irrigation Benefit Programme 1998-99. First instalment of Rs. 7.17 crores was released. Second Instalment was not released as State Government informed in November, 98 that they have reduced their budget for this project for 1998-99.

वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान

2634. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त "मास्टर प्लान" की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या "मास्टर प्लान" के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संसाधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, जो कि पूर्णत: गुजरात सरकार के स्वामित्व में है, को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के भागीदार राज्यों को लाभ देने वाले नर्मदा जल को काम में लाने के लिए गुजरात राज्य में सरदार परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।